जिला सैक्टर योजना/आयोजनागत/टी०एस०पी० संख्या- ७ ८५ /XV-2/01(15)/2006

प्रेषक,

विनोद फोनिया, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी, **ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, चम्पावत एवं देहरादून**, उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग- 02

देहरादून, दिनांक ७३ मई, 2011:

किश्य :— वित्तीय वर्ष 2011—12 में डेरी विकास विभाग को जिला योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (टीoएसoपीo) हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, (वित्त) के शासनादेश संख्या—209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31—3—2011 के कम में एवं आपके पत्र संख्या 376—78/लेखा—प्रस्ताव आयो0 टीएसपी/2011—12, दिनांक 23—05—2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011—12 में डेरी विकास विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण हेतु (जिला योजना) में अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ ₹ 6.68 लाख (₹ छः लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न जनपदवार एवं शर्तो अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

			धनराशि (लाख ₹ में
क0सं0	जनपद का नाम		धनराशि
1.	उधमसिंहनगर		3.06
2.	पिथौरागढ़		1.61
3.	चम्पावत		0.92
4.	देहरादून		1.09
		कुल योग :	6.68

(कुल ₹ छः लाख अड़सठ हजार मात्र)

1. उक्त जनपदवार निर्गत स्वीकृति सम्बन्धित सहायक निदेशक, डेरी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्टि करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कही आवश्यक हो सक्षम अधिकारी को स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय—समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृत परिव्यय के अनुरूप किया जायेगा।

वजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

2/-



- 3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखत नियमों, क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक,
 भौतिक एवं वित्तीय प्रगति उपलब्ध कराई जायेगी।

5. विभिन्न मदों में व्ययभार / देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मॉग के समय सही निर्णय लिया जा सके।

6. निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये कड़ी कार्यवाही व सद्यन अनुश्रवण किया जाये एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर—211(d) की अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अवमुक्त की जा रही धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि चालू निर्माण कार्यो पर तथा 20 प्रतिशत निर्माण कार्यो पर व्यय की जाये।

2— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में अनुदान संख्या—30 के अंतर्गत लेखाशीर्षक—2404—डेरी विकास—00—आयोजनागत—796—जनजाति क्षेत्र उपयोजना—91ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहारिताओं का सुदृड़ीकरण (जिला योजना)—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज-सहायता के नाम डाला जायेगा।

3— यह आदेश प्रमुख सचिव, (वित्त) के शासनादेश संख्या—209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31—3—2011 द्वारा निर्गत निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे है। भवदीय,

(विनोद फोनिया) सचिव।

संख्या : 754 /XV-2/01(15)2006 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 2. मण्डालायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
- 3. कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़,, चम्पावत एवं देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 4. स्टाफ ऑफिसर-प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
- ं. ानेजी सचिव-मंत्री, डेरी विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
- 6. निदेशक, डेरी विकास विभाग, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।
- 7. समस्त सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
- 8. वित्तु अनुभाग-4 / नियोजन विभाग / समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- . अ. मिदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।

10.गार्ड फाइल।

(जी0बी0 ओली) संयुक्त सचिव।

C